



रांजय कुमार सिंह
अध्यक्ष, पूर्णिया



धनंजय कुमार सिंह
उपाध्यक्ष, पूर्णिया



कृष्णनन्द सिंह
अध्यक्ष, बेतिया



राजीव रंजन भारती
अध्यक्ष, मधेपुरा



मो. अंजूम शमीम
दस्टि नेता, अकिंचन



प्रमोद मंडल
जिला उपाध्यक्ष सह अधिकारी



कन्हैया यादव
कार्यालय सचिव, कटिहार



रौशन कुमार
प्रभारी सुपील



कुन्दन कुमार मंडल
कार्यवाहक अध्यक्ष, कटिहार



यशपाल
अध्यक्ष, सिवान



करण कुमार
संगठन प्रभारी, मंगुर



.विकास कुमार
कदवा प्रभारी, कटिहार

चुनाव



चिन्ह

खाने से भरी थाली

Printing: Sanjay Design, KTR



चुनाव

चिन्ह

खाने से भरी थाली

अपना किसान पार्टी



जय लाल प्र० सिंह कुशवाहा
संस्थापक मह राष्ट्रीय अध्यक्ष



रंजीत कुमार सिंह
राष्ट्रीय महासचिव

संरक्षक मंडल



कमल सिंह



राकेश प्रसाद



रांजय सिंह

प्रधान कार्यालय- होटल जय, न्यू मार्केट, कटिहार- 854105 (बिहार)

● 9934467138 ● 9113704469

facebookpage-apnakisanparty.india apnakisanparty.india@gmail.com

चुनाव



चिन्ह

➤ खाने से भरी थाली <

अपना किसान पार्टी

प्रधान कार्यालय- होटल जय, न्यू मार्केट, कटिहार- 854105 (बिहार)

9934467138 9113704469

facebookpage-apnakisanparty.india apnakisanparty.india@gmail.com

अपना किसान पार्टी

एक दृष्टि में...

“अपना किसान पार्टी” का मानना है कि, भारत के आबादी की सबसे भारी संख्या खेती में लगी हैं, इनके जीवन बेहतर करने की ‘विचार धारा’ योजना बनाने वाली देश की एक मात्र राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना जिला कटिहार बिहार राज्य की धरती पर दिनांक 21 जुलाई 2018 को हुई है। आम और तमाम लोगों के लिए राष्ट्रवाद हर क्षेत्र में चल रहे गैर बराबरी को समाप्त कर देश के प्रति निष्ठा हमारा लक्ष्य है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त कर सबसे बड़ी आबादी की बेहतरी का प्रयास ही मेरा उद्देश्य है। देश के लोकतंत्र को मुख्यधारा से बड़ी आबादी के जीवन शैली को सही दिशा दिखाना जो उनके फायदे का हो बिना दिग्भ्रमित किये नेतृत्व करना है “सर्वे भवन्तु सुखिनः” लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से संगठन बना कर सत्ता में भागीदारी लेना एवं सत्ता के माध्यम से नये सिरे से कानून बना कर देश की बड़ी आबादी को बेहतर करना है। इसलिए, आप सभी “अपना किसान पार्टी” का सदस्य बन कर इस मिशन को पूरा

1

करने का आग्रह करते हैं।

आजादी के 72 वर्ष बाद भी किसानों के उत्पादन का दाम व्यापारी तय करते हैं, इसका कारण है भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति का नहीं बनना। खपत के आधार पर उत्पादन तय नहीं हुआ, जिस प्रकार उद्योग में होता है। बाढ़ से ग्रामीण क्षेत्र की आबादी, खेती की बर्वादी होती है। इसलिए कि बाढ़ के पानी को बड़ी-बड़ी केनाल के द्वारा बहाने का इन्तजाम नहीं हुआ। फसल बीमा योजना मकरजाल की तरह बनाया गया है जिससे किसानों को इस योजना के लाभ लेने की जगह देने पर गए।

अतः इन सभी समस्याओं के लिए स्पष्ट एवं पुख्ता कानून की आवश्यकता है। जो अभी तक इसलिए नहीं बना क्योंकि किसानों का कोई प्रतिनिधि संसद, विधान सभा में नहीं है। जिनको किसान वोट देकर प्रतिनिधि बनाए हैं, वे अपना काम करते हैं या फिर पार्टी या सरकार का। उन्हें किसानों से वोट के सिवाय कोई लेना देना नहीं है। इसलिए, जब किसान प्रतिनिधि चुनकर संसद में जाएंगे तो वे अपने पक्ष की बात रखकर

2

कानून बनाएँगे तभी होगा किसान का भला।

आजादी के बाद न जाने कितने दल बने जिन्होंने जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद पर आधारित सिद्धान्त पेश किए। समाज की बड़ी आबादी को जाति-धर्ममें बांट कर वोट लेते रहे और हम किसान जो एक ही पेशा करते हैं इसके लिए किसी ने कोई बोली नहीं बोली। राज्यसभा में हर सेक्टर के बेहतर के लिए एक-एक सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ तक कि अल्प आबादी किन्नर (हिजड़ा) को भी एक राज्य सभा सदस्य मनोनीत किया जाता है। किन्तु सम्पूर्ण भारत में जहाँ 70% आबादी कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उनकी बेहतरी के लिए राज्य सभा में एक भी सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था नहीं है, सरकारी सेवा में लगे व्यक्ति का तन्खाह उसके खाने-पीने, रहने सहने, दवाई नाई, धोबी, बच्चों की पढ़ाई देशाटन मतलब बेहतर जिन्दगी के सभी मुक्कम्मल इन्तजाम के आधार पर तय होता है। लेकिन किसान के उत्पादन का दाम लागत के बराबर या 5% बढ़ोतरी पर तय होता है। क्या किसान बच्चे पैदा नहीं करते?, क्या किसान बच्चे को नहीं पढ़ाते?, क्या किसान बच्चे को कपड़े नहीं पहनाते?, क्या किसान बीमार

3

नहीं होते?, क्या किसान को रहने के लिए घर नहीं चाहिए?, क्या किसान के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते?, क्या किसान देशाटन धर्म स्थान नहीं जाते? किन्तु इन बातों से किसी भी राजनीतिक दल या किसी सरकार को कोई मतलब नहीं है। उसे तो केवल उत्पादन का लागत ही लौटाना है जिससे वह पूरी जिन्दगी कंगाल बना रहे।

बिगत वर्षों में हमारे कई नेता किसान की रहबड़ी करने निकली जैसे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवी लाल इत्यादि लेकिन इन लोगों ने किसानों को सत्ता में भागीदारी लेने के लिए नहीं ललकारा। जिसका नतीजा हुआ कि किसान के जीवन को नहीं जानने वाले नेता बनते रहे और किसान की समस्याएँ धरी की धरी रह गई। कुछ छोटे-छोटे नेता पूरे देश में स्थानीय समस्या को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन, किसान यात्रा निकालते रहे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर किसान वहीं नजर आए जहाँ से वे चले थे। यही स्थिति आज भी बरकरार है। किसानों को अपने कर्तव्यों के आधार पर भी अधिकार मांगने की बात ही नहीं कही गयी। जिसका कारण है कि हम

सत्ता से बाहर रहकर केवल मांगते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं। जहाँ कानून बनता है वहाँ हमारी उपस्थिति ही नहीं है तो मेरे पक्ष में कानून बनेगा कैसे। वर्ष 1966 में इन्दिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनी उन्होंने 1967 में राष्ट्रीय उद्योगनीति बनाई। किन्तु कृषि प्रधान देश में भारतीय राष्ट्रीय कृषिनीति आज तक नहीं बनी। किसान हर वर्ष बाढ़ से बरवाद होता है। किन्तु राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति नहीं बनी। देश के हर क्षेत्र में बीमा योजना कानून बना किन्तु किसान के लिए जो फसल बीमा कानून बना वह आज तक किसानों को पता भी नहीं है, कि फसल बीमा योजना क्या होता है। किसानों के पुत्र शरहद पर देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं किन्तु उनके मारे जाने पर केवल दो दिन के लिए शहीद का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद परिजन का सूधी लेने वाला काई नहीं होता है। उसे शहीद मौखिक कहा जाता है शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह छोटे लोगों की सन्तान है। उसे एक फौजी कहा जाता है। किसी आदरणीय पिता के सम्मानित पुत्र नहीं हो सकते। शिक्षा की हालत ऐसी है कि बड़े लोगों के लिए बड़ी शिक्षा, मझौले लोगों के लिए मध्यम शिक्षा, छोटे लोगों के

लिए खिचड़ी शिक्षा। इस परिस्थिति में गांव में बसे लता मंगेस्कर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, ई. विश्वरैया, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसी मेघा शक्ति धरी की धरी रह जाती है। इसे आगे लाने का किसी पाटी, किसी सरकार का मकसद ही नहीं रहा। सर्वे भवन्तु सुखिन पर कोई मंशा ही नहीं बना, ये हमारे किसान भाईयों का बड़ा दुर्भाग्य है।

वसुधेव कुटुम्बकम पर कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया। देश की सुरक्षा के नाम पर जनता को खूब डराया जाता है जिससे जनता हमारी बात सुने। पड़ोसी देशों से मित्रता नहीं बढ़ाई। विदेशिक नीति पर गम्भीर (चिंतन, पुर्णभाव लोकन वर्तमान, परिपेक्ष, में आवश्यकता महसूस किया जाना आवश्यक है।) जिसने देश की सुरक्षा पर बेतहासा खर्च को रोका जा सके। देश की जनसंख्या के लिए कोई संवेदनशील संवेदना से भरा, प्यार से भरा कोई सौंच नहीं बनाई गई। कोई कानून नहीं बना। जिससे हम पूरी आबादी को पूर्णरूप से चौतरफा विकसित कर सके।

आजादी के 72 वर्षों बाद भी हम स्वच्छ जल का प्रबंध नहीं कर पाये, कुपोषण से देश की 39% प्रतिशत

की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं दिला पाए। बच्चों को अपने अधिकार नहीं दिला पाए, बुढ़े माता पिता पर हो रहे अत्याचार पर कोई अंकुश नहीं लगा पाए। नदियों की तबाही से आबादी को कोई निजात नहीं दिला पाए।

देश के नागरिक जिस वर्ष वयस्क होता है, उसके उल्टे वर्ष उसकी मेघा शक्ति के अनुसार उसकी इच्छा के अनुसार कर्तव्य निर्वहन का पुख्ता इन्तजाम नहीं हुआ। मतलब न बेकार रहेगा न बेरोजगारी की समस्या ही। देश में गर्भवती महिलाओं को संरक्षण, संवर्धन पर कानून नहीं बना। कुपोषण के शिकार से देश के दीनहीन बड़ी संख्या में है। उसके घर जो बच्चा पैदा होता है। वह रोगग्रस्त पैदा होता है। जबकि इन्हीं दीनहीन के बच्चे शरहद पर राफेल ऐसे युद्ध आयुध चलाने जाएंगे। यदि स्वस्थ बच्चा पैदा होगा तभी, तो स्वस्थ भारत बनेगा। इसके लिए पुख्ता कानून की जरूरत है जब महिला गर्भधारण करने के 15 महीने तक सरकारी खर्च से जच्चा-बच्चा को उच्च स्तरीय पालन पोषण कर सके। देश में जहाँ बड़ी आबादी है, वहाँ स्वास्थ्य की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। इसपर बड़ी आबादी को बड़ी बीमारी का

सामना नहीं करना है बल्कि उसे मर जाना है ।

देश में अपने पेशे के आधार पर किसान को छोड़ कर दूसरा कोई भी वर्ग आत्म हत्या नहीं करता है । किसान आज भी लगातार खेती में हानि होने पर आत्महत्या कर रहा है । चाहे वह एनडीए की सरकार रही हो, या यूपीए की । कोई ठीकेदार, कोई नौकरशाह, कोई उद्योगपति कोई विजनेस मैन, कोई रंगदार, दलाल कभी अपने पेशे के कारण आत्महत्या नहीं करते । क्योंकि उनके अपने पेशे में दिन दुगुनी रात चौगुनी होती है । आत्म हत्या केवल अन्न दाता जो देश को खिलाते हैं वही करते हैं । अपनी सुरक्षा के ख्याल रखे बगैर कोरोना ऐसी महामारी में जबकि पूरा देश घर में रह रहा है ऐसी परिस्थिति में किसान, अन्न, फल, सब्जी, दूध खेतों से उत्पादन कर देशवासियों का घर पहुँचा रहे हैं । यह काम भगवानरूपी किसान कर रहा है जो देश की कुव्यवस्था के कारण आत्महत्या करता है । अतः व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता की भागीदारी आवश्यक है जबतक सत्ता में किसान नहीं आएंगे तब तक व्यवस्था नहीं बदल सकती ।

इसलिए किसानों को अपनी बोली बोलनी

होगी, किसानों को प्रवक्ता बनना होगा, सरकार में भागीदारी लेना होगा, एम.पी./एम.एल.ए. बनना होगा । जहाँ कानून बनता है वहाँ किसानों की उपरिस्थिति नहीं है, इसलिए वहाँ प्रतिनिधि बनकर जाना होगा । सौ में सत्तर किसान हैं सत्तर भाग हमारा है, एवं जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी भागीदारी का नारा बुलन्द करने पर ही किसानों का भला हो सकता है ।

अब सब्र की बांध को ध्वस्त कर सीधे और सीधे किसान एवं देश हित में किसान पार्टी का गठन कर सौ में सत्तर सीटों पर चुनाव लड़कर एम.पी./एम.एल.ए. बना कर व्यापक रूप से आम और तमाम लोगों की सेवा करने के लिए तैयार होना होगा । तमाम किसान भाई गंभीरता से सोचिए और किसी बड़े नेता मसीहा की प्रतीक्षा न करें । आप स्वयं नेता बने अब तक दूसरे के लिए संगठन बनाए हैं अब अपने लिए संगठन बनाए । चुनाव लड़ कर जीते विधान सभा एवं संसद में किसानों की पीड़ा के आधार पर बेहतरी के लिए कानून बनावें । क्योंकि अबतक किसानों के हित में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी ।

निवेदन के साथ-

अपील

1. अपना किसान पार्टी का सदस्य बनें।
2. गर्व से कहो हम किसान हैं।
3. किसान हिन्दू हो या मुसलमान अभिवादन हो जय किसान।
4. होई वहीं नृप जिसे हम चाहे, हम है भारत भाग्य विधाता।
5. जो किसान की बात करेंगा। वही देश पर राज करेगा।
6. सौ में सत्तर किसान है, सत्तर भाग हमारा है। धन धरती और राज पाट पर सत्तर हिस्से हमारे हैं।
7. जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी।
8. राजनीतिक पार्टियाँ राजनीतिक भ्रष्टचार बन्द करो।

हमारा ऐलान

1. बहुत हो गया वादों के नारे, अब नहीं चलेगा कोई वाद, अब होगी केवल वास्तविकतावाद। वास्तविकता की चादर पर सोएगा अब हिन्दुस्तान। ढोल बजाकर कहने आए हैं, सम्भलों तो सम्भलों नहीं तो खोल देंगे तेरा पोल।

एजेण्डा

1. भारतीय राष्ट्रीय कृषिनीति बनाओ।
2. भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बनाओ
3. फसल बीमा योजना आम और तमाम किसानों के लिए बनावें। मसौदा पार्टी तय करेगी।
4. समान्य शिक्षा नीति लागू हो,
5. मंडल कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार 52 प्रतिशत आरक्षण लागू करें।
6. मजदूरों का काला कानून आपस लो, काम के घंटे आठ करो।

लक्ष्य

1. किसान की बात नहीं करना देश का अपमान है।
2. किसान जातिनहीं खेत है, खेत नहीं उपजेगा तो खाओगे क्या ?
3. किसान इंसान रूपी भगवान है, इसकी सहायता करना पूजा के समान है।
4. कृषि-ऋण माफ करना एक धोखा है, किसानों को बदहाल बनाए रखने का एक सौदा है।
5. जबतक न होगी किसान की सरकार, किसानों को तब तक अच्छे दिन का करना होगा इन्तजार।
6. किसान कर्तव्य के आधर पर सरकार में भागीदारी चाहती है।
7. जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
8. दृढ़ संकल्प, एकता, संघर्ष, अनुशासन हमारा अमोध बल है।



विश्वकर्मा शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	डा. प्रेम कुशवाहा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह प्रबक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता, हाईकोर्ट पटना	नारायण रिंग प्रदेश अध्यक्ष सह वरिष्ठ अधिवक्ता	बी. बी. रिंग कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष
शंकर सिंह प्रदेश महासचिव	सूरज प्रसाद सिंह प्रदेश सचिव	पंकज कुमार राय प्रदेश अध्यक्ष, तकनीकी प्रकोष्ठ	नूर आलम प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
अजय पासवान प्रदेश अध्यक्ष, दलित प्रकोष्ठ	शशि कु. श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष, कला संरक्षित	प्रेम कुमार युवा प्रदेश अध्यक्ष	ओकेश अहमद करौरी 5 जिलों के प्रभारी
बिमल कु. मेहता जिला अध्यक्ष, अररिया	मो. अकबर जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ^{अररिया}	राम प्रवेश सिंह जिला अध्यक्ष, कटिहार	भोला नन्द विश्वास जिला उपाध्यक्ष, कटिहार